

to associate with the Committee on Public Undertakings of this House for the unexpired portion of the term of the Committee ending on the 30th April, 1979—vice Shri Deoraj Patil died and do communicate to this House the name of the Member so nominated by Rajya Sabha."

*The motion was adopted.*

**SHRI ANNASAHAB GOTKINDE** (Sangli): I am on a point of order.

**MR. DEPUTY - SPEAKER:** What is it?

**SHRI ANNASAHAB GOTKINDE:** The motion mentions the name as Shri Deoraj Patil. There was no such Member. He was Shri Deorao Patil.

**MR. DEPUTY - SPEAKER:** It is a printing mistake. It must be Shri Deorao Patil. It will be corrected. Now the next item.

14.31 hrs.

**DEMANDS FOR EXCESS GRANTS** (GENERAL), 1976-77

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE** (SHRI SATISH AGRAWAL): Sir, on behalf of Shri H. M. Patel I beg to present a statement showing Demands for Excess Grants in respect of the Budget (General) for 1976-77.

**MR. DEPUTY - SPEAKER:** Now, Matters under Rule 377.

#### MATTERS UNDER RULE 377

##### (i) REPORTED CANCELLATION OF CERTAIN TRAINS IN OLAVVAKKOT DIVISION OF SOUTHERN RAILWAY FOR WANT OF COAL.

**SHRI A. SUNNA SAHIB** (Palghat): Sir, I would like to draw the attention of the hon. Railway Minister to the matter of urgent public importance. In the Mathrubhoomi, Malayalam daily of 13-2-1978, it has been mentioned that 50 passenger trains and 30 goods trains have been cancelled for want of coal in Olavvakkot Division of Southern Railway, on account of which thousands of passengers and goods worth several lakhs of rupees have been put to difficulties and destruction respectively. On account of paucity of coal, trains from Cochin to Shoranur, Cochin to Mettupalayam are cancelled. I need not say that this route is the livewire route of Malabar part of Kerala for trade and business. I apprehend that trains between Cannanore to Trivandrum, Ernakulam to Trichur will also be cancelled. If shortage

of coal is not remedied immediately, the entire economy of Kerala will be in doldrums. Even as it is, the coal supply has to come from Bihar coal mines. The transportation of coal will take at least 15 days before these trains are restored.

I request a statement from the hon. Minister of Railways assuring immediate despatch of coal to Southern Railway so that the misery of passengers can be alleviated and goods supply revive forthwith.

##### (ii) WORKING OF FERTILIZER PLANNING AND DEVELOPMENT LTD., SINDRI.

**श्री बुधराज (कटिहार):** उपाध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर प्लानिंग एण्ड डिवेलपमेंट लिमिटेड, सिन्दरी के वैज्ञानिक अनुसंधान डिजाइन तथा इंजीनियरिंग में प्रगति रहे हैं। एक अप्रैल, 1978 से वह स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहा है। इसके पूर्व यह भारतीय खाद निगम की पांच इकाइयों में से एक था। इस में कुल तीन हजार से अधिक कर्मचारी नियुक्त हैं जिन में करीब 45 इंजीनियर तथा 300 वैज्ञानिक भी शामिल हैं। बेतन के रूप में करीब इसे प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं। इसकी मुख्य धारा कैप्टलिट उत्पादन तथा खाद के डिजाइन और इंजीनियरिंग से होती है।

यह स्पष्ट है कि इस संस्थान की दिनों दिन भरस्की हो गई है लेकिन पिछले एक साल से यह लड़खड़ा रहा है। अभी इसके पास काम नहीं के बराबर है। बम्बई हाई गैस पर आधारित चार फर्टिलाइजर प्रोजेक्टों को जो करीब 1200 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट है विदेशी कम्पनियों को देने पर यहां के इंजीनियरों को काम नहीं के बराबर ही रहेगा। साथ साथ यह काम विदेशी कम्पनियों को देने पर करीब करीब 600 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा में विदेशी कम्पनियों को विदेशी साज सामान खरीदने तथा डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए देने पड़ेंगे। लेकिन यदि इन प्रोजेक्टों को उक्त संस्थान को सौंपा जाता तो विदेशी मुद्रा में बहुत कम रुपये ही विदेशी कम्पनियों को लाइसेंस के रूप में देने पड़ते। दूसरी बात यह है कि यदि इन प्रोजेक्टों की क्षमता 1350 टन प्रति दिन के बजाय 900 टन प्रति दिन रखी जाती तो यह कार्य उक्त संस्थान द्वारा ही किया जा सकता था। अभी तक इस संस्थान ने दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप, गोरखपुर, टाम्बे, नंगल, सिन्दरी, प्राधुनिकीकरण इत्यादि प्रोजेक्टों का काम सफलतापूर्वक किया है। नंगल सिन्दरी 900 टन प्रति दिन अमोनिया उत्पादन करने वाले प्लांट हैं तथा रामागुडम और तालचर जो कोयले पर आधारित 900 टन वाले अमोनिया प्लांट हैं कुछ महीने में ही उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे। 1965-70 तक उक्त संस्थान को 6-7 फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट मिले जिन में कुछ बुनियादी डिजाइन की जानकारी विदेशी कम्पनियों से भी गई और अधिक से अधिक उपयोग प्रपने वहां की मशीनरी और टेक्नालाजी का किया गया। विश्व के विख्यात से विख्यात डिजाइन प्रतिष्ठान भी कुछ न कुछ जानकारी दूसरों से खरीवते हैं और अपने

[श्री यवराज]

यहां उसे अपनी इंजीनियरिंग के अनुभव पर उसका विकास करते हैं। एक पी डी आई एल में भी 1970-71 तक यही प्रणाली चलती रही। जब पानीपत और भटिंडा के दो फटिलाइजर प्रोजेक्ट इस संस्थान को नहीं दिए गए और पूरा का पूरा प्रोजेक्टर जापानी कम्पनी टोयो को दिया जाने लगा तब उस समय भारतीय खाद निगम के बेयरमैन ने इस प्रस्ताव का धोर विरोध किया और उन्होंने राय दी कि यह दोनों प्रोजेक्ट भारतीय-प्रतिष्ठान ही कर सकता है। उनकी बात सच निकली जब की ठीक पानीपत और भटिंडा की तरह दो प्रोजेक्ट नांगल विस्तार और सिन्धी प्राधुनिकीकरण जो इस प्रतिष्ठान द्वारा किये गये हैं अपने निश्चित समय पर पूरे हो गये हैं पर भटिंडा और पानीपत जो जापानी कम्पनियों द्वारा किये जा रहे हैं वे अपने निश्चित समय से 36 महीने पीछे हैं।

जब बम्बई में 2700 टन घमोनिया प्लांट बनाना ही था तो उसे 1350 टन के दो प्लांट के बजाय 900 के तीन प्लांट दिये जा सकते थे जिससे यह काम भारतीय कम्पनी द्वारा ही किया जा सकता है। रामागुण्डम तथा तालचेर प्रोजेक्टों में इसी प्रकार से भारतीय कम्पनी ने विदेशों से टक्नीकल नो हाऊ ले कर पूरा काम अपने से किया। यह कार्य भी मुख्य रूप से इसी संस्थान को दिया जा सकता था जो कुछ ग्राहक से टेक्नीकल नो हाऊ ले कर अपने से कर सकता था। लेकिन ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट विदेशी कम्पनियों को दिये जा रहे हैं और इस संस्थान को सिर्फ नक्शा खींचने का काम मिलेगा वह भी सिर्फ लोगों की प्रांथ में धूल झोंकने के लिए कि एक 0 पी 0 0 0 आई 0 एल 0 को भी कुछ काम दिया जा रहा है। भारतीय परिवेश में 1350 टन की क्षमता वाला प्लांट ठीक से चल सकेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसके प्रत्येक स्पेयर पार्ट्स बाहर से मंगाने होंगे। उदाहरण स्वरूप बरीनी खाद कारखाने का कारबन डाइआक्साइड गैस कम्प्रेसर उसका स्पेयर पार्ट्स मंगाने में तीन महीने से भी अधिक लग गये, और तब यह कम्प्रेसर बैठा था। इस तरह की घसुविघातों निश्चित रूप से ही इस प्रोजेक्ट में भी रहेंगी।

जब इतने महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिये जा रहे हैं तब दुर्भाग्य है कि इस संस्थान का अभी तक 9 महीनों के बाद भी कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त नहीं किया गया। 3 महीने पूर्व सिर्फ एक पार्ट टाइम बेयरमैन की नियुक्ति हुई है जिन्हें इस संस्थान की कार्य विधियों को देखने का बहुत कम समय है।

अभी उक्त संस्थान का कार्यभार प्रणाली निदेशक को सौंपा गया है जो कुछ दिनों पूर्व जनरल मैनेजर थे। जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से चारों ओर विशेष ही विशेष है तथा धाकड़े भी यह दिखाते हैं कि इस संस्थान की प्राय 1975-76 की प्रपेक्षा बहुत कम हो गई है।

जहां तक इसके कुछ विभागों को खूब रोजगार मिलने के लिए दिल्ली से घाने की बात है वह किलहाल जंचती नहीं है। काम साने के लिए तेज और योग्य भ्रफसतों और इंजीनियरों की जरूरत है न कि दिल्ली में अधिक भ्रादभियों से भ्राफिस खोलने की। अभी तक सिन्धी में रह कर इसे करोड़ों का काम मिलता रहा है। सिर्फ जरूरत है सिन्धी के विकास की और इसके लिए राज्य सरकार पूरा सहयोग करने के लिए तयार है। दिल्ली में अधिक बढ़ा भ्राफिस रखने से अभी सिर्फ भ्राफिस किराया देने के लिए 6 लाख ४0 सालाना देने पड़ेंगे तथा अन्य खर्च भ्रलग होंगे। दिल्ली में अभी इस संस्थान के नाम पर जितने करीब 80 स्टाफ हैं, उन्हीं से यहां के व्यापार का काम पूरा चल जायेगा। अतः इसे विस्तृत करने की कोई आवश्यकता नहीं दिख पड़ती है।

भारत के फटिलाइजर प्रोजेक्टर के भ्रलावा इस संस्थान में बर्मा, फिलिपीन, इराक और श्रीलंका इत्यादि बाहर के देशों में फटिलाइजर का प्रारूप तैयार किया है। अभी अभी पुर्तगाल में भी एक प्रारूप भेजा गया है। इस संस्थान के केटेलिस्ट बुनगेरिया में भी भेजे गये हैं।

यह संस्थान बिहार की प्रतिष्ठा का खोनक है और इसको किसी भी कीमत पर नष्ट नहीं होने देना है। यह कैसी विडम्बना है कि इसका पंजीकृत मुख्यालय सिन्धी होते हुए भी एक भी बोर्ड की मीटिंग सिन्धी में नहीं हुई और सारी की सारी मीटिंगें दिल्ली में ही हुईं।

#### (iii) INDO-BANGLADESH AGREEMENT ON THE PRINCIPLES OF DEMARCATION OF BOUNDARY BETWEEN THE TWO COUNTRIES AND EXCHANGE OF CERTAIN ENCLAVES.

SHRI AMAR ROY PRADHAN (Cooch Behar) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for permitting me to raise the following matter of urgent public importance under Rule 377.

It was published in the newspapers, namely, Amrita Bazar Patrika, Calcutta Edition, dated 21st of October, 1978, Ananda Bazar Patrika dated 18th of November, 1978 and Jugantar Patrika dated 28th of November, 1978 and Satyajugo dated the 17th of December, 1978, that the Government of India have finalised a legislation to give effect to the Indo Bangladesh Agreement arrived at between the ex-Prime Minister of India and the then Bangladesh Prime Minister on 16th May 1974, on the principles of demarcation of boundary between the two countries and exchange of several enclaves.

It is learnt that the Government of India is going to introduce a Constitution Amendment Bill which will only involve the Schedules and are expected to follow the Constitution (Ninth Amendment)